जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 37 संख्याः 359 प्रभात अजमेर, शुक्रवार 7 अगस्त, 2026 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

जैनरेशन ज़ैड में सरकार की साख बचाने आगे आए मोहन भागवत

मुम्बई में छात्रों से एक संवाद कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जैनरेशन ज़ैड को समर्थन दिया और युवाओं से संवाद पर जोर दिया

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 अगस्त। नरेन्द्र मोदी सरकार जैन-ज़ैड के मुद्दे पर पूरी तरह से घबराई हुई नज़र आ रही है।

सरकार की विश्वसनीयता अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, इन हालात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत को स्वयं मोर्चा संभालना पड़ा। मुंबई में आयोजित एक युवा सम्मेलन में उन्होंने जैन-ज़ैड का समर्थन करते हुए कहा कि युवा "हमारे अपने हैं" और यदि उनकी कोई समस्या है तो उस पर संवाद होना चाहिए।

सरकार जो संदेश आंदोलनरत छात्रों और युवाओं तक नहीं पहुंचा सकी, उसे संघ प्रमुख के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की गई।

इसके बावजूद सरकार राहुल गांधी के युवाओं तक बढ़ते संपर्क और जैन-ज़ैड के प्रति उनके खुले समर्थन को लेकर चिंतित बनी हुई है।

इलाहाबाद (प्रयागराज) में छात्रों से प्रस्तावित राहुल गांधी की मुलाकात पर भी अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है।

- कांग्रेस ने मोहन भागवत के, छात्रों से संवाद कार्यक्रम पर भी टिप्पणी की और कहा कि मोहन भागवत को प्र.मंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को निर्देश देना चाहिए कि वे प्रदर्शनकारी युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लें और उन्हें परेशान न करें।
- राहुल गांधी के जैनरेशन ज़ैड के प्रति खुले समर्थन और युवाओं में उनकी बढ़ती साख को लेकर केन्द्र सरकार में भारी चिंता है।
- इसी चिंता के कारण यूपी सरकार ने प्रयागराज में राहुल गांधी के "छात्रों की गूंज" कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है, हालांकि, कांग्रेस ने दावा किया कि कार्यक्रम तय समय के अनुसार ही होगा।

हालांकि, कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा। यह अभियान कोटा से शुरू हुआ था और अब आगामी सप्ताहांत में प्रयागराज पहुंचेगा।

कांग्रेस का कहना है कि योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत के अनुयायी हैं। ऐसे में बड़े-बड़े बयान देने के बजाय भागवत को योगी आदित्यनाथ से कहना चाहिए कि वे इस कार्यक्रम और छात्रों के साथ संवाद की अनुमति दें।

सवाल उठता है कि आखिर यह घबराहट क्यों?

कांग्रेस का यह भी कहना है कि संघ प्रमुख होने के नाते मोहन भागवत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निर्देश देना चाहिए कि वे आंदोलनरत छात्रों को परेशान करना बंद करें, उनके खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लें और यह सुनिश्चित करें कि विरोध प्रदर्शन करने के कारण उन्हें प्रताड़ित न किया जाए।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि भाजपा हर स्थिति में अपनी ही चलाना चाहती है, "चित भी मेरी, पट भी मेरी।" उनका कहना था कि लोकतंत्र में यह रवैया नहीं चल सकता।

उधर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमित शाह के संसद के दोनों सदनों से लगातार अनुपस्थित रहने को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि उनकी अनुपस्थिति के कारण लगातार हंगामा, स्थगन और कामकाज में बाधा आ रही है तथा कोई सार्थक विधायी कार्य नहीं हो पा रहा है।

विपक्ष ने परिसीमन (डिलिमिटेशन) विधेयक पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है।

इसके बावजूद संसदीय कार्य मंत्री ने आज फिर राहुल गांधी से संपर्क कर इस विधेयक पर विपक्ष का समर्थन मांगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक सारे अतिक्रमण दो माह में हटाएं- हाई कोर्ट

जयपुर, 6 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यू सांगानेर रोड पर सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक की 100 फीट चौड़ी रोड सहित, यहाँ स्थित विश्वा नगर की 30 फीट चौड़ी रोड पर अवैध निर्माण के मामले में जेडीए को दो महीने में अतिक्रमण हटाने को कहा है। इसके साथ ही, अदालत ने जेडीए सचिव को कहा है कि वे दो माह बाद पालना रिपोर्ट पेश करें। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश गुरुवार को सुरेश चन्द रावत व अन्य की पीआईएल पर दिए।

- जेडीए की ओर से अतिक्रमण हटाने का प्लान चार्ट पेश कर साढ़े पाँच माह का समय मांगा गया था।

सुनवाई के दौरान, जेडीए के अधिवक्ता अमित कुडी ने अदालत में अतिक्रमण हटाने का प्लान चार्ट सहित पेश करते हुए साढ़े पांच महीने का समय मांगा। उन्होंने अदालत को बताया कि सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक किन-किन स्थानों पर रोड की चौड़ाई कितनी-कितनी है। इसलिए पीटी सर्वे, मास्टर प्लान के अनुसार अतिक्रमणों का सत्यापन करने और धारा 72 के तहत अतिक्रमियों को नोटिस जारी करने सहित अन्य कार्रवाई के लिए समय दिया जाए। अदालत ने जेडीए का पक्ष सुनने के बाद उसे दो महीने में सभी अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कई नामचीन हस्तियों ने थामा कांग्रेस का दामन

कांग्रेस के मुख्यालय पर हुई एक प्रैस कॉन्फ्रैंस में कांग्रेस के प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा व यूपी के एआईसीसी प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम ने इन सभी का स्वागत किया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 अगस्त। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा और उत्तर प्रदेश के एआईसीसी प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम ने गुरुवार को एआईसीसी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस में शामिल होने वाले कई नेताओं का स्वागत किया। इनमें सेवानिवृत्त आईएएस, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी राहुल गांधी की सक्रियता को देखकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं।

इनमें डॉ. अनूप कुमार आंबेडकर शामिल हैं, जो बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की कई राज्य इकाइयों के प्रभारी रह चुके हैं। इनके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के वकील मयंक यादव और अधिवक्ता श्रेय यादव भी कांग्रेस में शामिल हुए। श्रेय यादव ने छात्र आंदोलनों से जुड़े मामलों में वकालत की है, जिनमें से लगभग 25 प्रतिशत मामलों में उन्होंने बिना कोई फीस लिए पैरवी की।

- इनमें बसपा की कई राज्य इकाइयों के प्रभारी रहे, डॉ. अनूप कुमार अंबेडकर, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मयंक यादव एवं श्रेय यादव प्रमुख हैं।
- इसके अलावा कई रिटायर्ड अफसरों ने और जाने माने किसान नेता रोहित जाखड़, आप के सोशल मीडिया हैड वकार चौधरी ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।
- यूपी के रिटायर्ड आईपीएस बीपी अशोक व उनके पिता, जिन्होंने इंडियन पोलिटिकल जस्टिस पार्टी बनाई थी, ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया।

कांग्रेस में शामिल होने वालों में उत्तर प्रदेश के पीसीएस अधिकारी सुनील कुमकर वर्मा भी हैं, जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। इनके अलावा, पंजाब के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे चौधरी खुशी राम भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं।

उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी बी. पी. अशोक ने भी कांग्रेस का दामन थामा। उनके पिता भी आईपीएस अधिकारी थे। दोनों ने मिलकर इंडियन पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी बनाई थी, जिसका अब कांग्रेस में विलय हो रहा है।

राजेन्द्र पाल गौतम ने किसान नेता रोहित जाखड़ का भी परिचय कराया, जिन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर पंजाब के किसानों का नेतृत्व किया था।

इस अवसर पर केरल के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सुदेश कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था और उन्हें खुफिया मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। कांग्रेस में शामिल होने वालों में आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया प्रमुख

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दीपके ने लॉन्च किया "क्या बोलती पब्लिक" अभियान

दीपके ने कहा कि सीजेपी के अभियान का फोकस बेरोज़गारी और शिक्षा सुधार होगा, जिसमें जनता की आकांक्षाओं को जानने का प्रयास किया जाएगा

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 अगस्त। जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे को अपनी बड़ी सफलता बताते हुए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने गुरुवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी अगले महीने देशव्यापी "क्या बोलती पब्लिक" अभियान शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के जरिए देशभर के लोगों से संवाद किया जाएगा और शिक्षा सुधार के साथ-साथ बेरोजगारी को राष्ट्रीय स्तर का प्रमुख मुद्दा बनाया जाएगा।

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित अपने आवास पर पार्टी की दो दिवसीय कोर कमेटी की बैठक के समापन के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में दिपके ने यह घोषणा की। इस दौरान सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास, प्रवक्ता आशुतोष रांका और पार्टी के अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

- मुम्बई में संघ प्रमुख मोहन भागवत के छात्रों से संवाद कार्यक्रम पर दीपके ने कहा, इसमें देर हो गई है, उन्हें छात्रों से 20 जुलाई को बात करनी चाहिए थी, जब पुलिस ने छात्रों को पीटा था।
- अभिजीत दीपके ने अपने निवास पर सीजेपी के प्रमुख पदाधिकारियों की एक बैठक ली, जिसमें सौरभ दास, आशुतोष रांका व अन्य लोग शामिल हुए थे।
- अनुमान है कि भारत की 1.4 अरब की जनसंख्या में जैनरेशन ज़ैड और 35 साल से कम उम्र के लोगों की काफी बड़ी तादाद है और 2029 के लोकसभा चुनाव के समय ये लोग सबसे बड़ा वोट बैंक होंगे।

दीपके ने कहा, "क्या बोलती पब्लिक" अभियान के दौरान हम जानेंगे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पांचना बाँध से पानी छोड़ने पर जनहित याचिका निस्तारित

जयपुर, 6 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने पांचना बांध से पानी छोड़ने के विवाद के मामले में दायर जनहित याचिका गुरुवार को निस्तारित कर दी। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश विधायक रामकेश मीणा व अन्य की जनहित याचिका पर दिया।

- अदालत के आदेश की पालना में जिला कलैक्टर ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया।

सुनवाई के दौरान, अदालती आदेश के पालन में जिला कलेक्टर का शपथ पत्र पेश हुआ था। खंडपीठ ने जिला कलेक्टर के शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लेकर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर नाराजगी जताई थी। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा था कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आरक्षण विरोधी ऑनलाइन मुहिम सड़कों पर उतरती दिख रही है

नागपुर से लेकर लखनऊ तक और जयपुर से लेकर विशाखापट्टनम तक आरक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 अगस्त। नागपुर से लेकर लखनऊ, जयपुर और विशाखापत्तनम तक देश के कई शहरों में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच, जाति-आधारित आरक्षण के खिलाफ एक समानांतर ऑनलाइन अभियान भी तेजी से गति पकड़ रहा है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ, आरक्षण विरोध की बढ़ती आवाजें भारत की सबसे संवेदनशील राजनीतिक बहसों में से एक को फिर से केन्द्र में ला सकती हैं।

पिछले कुछ सप्ताहों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जो पहली नजर में अलग-अलग प्रतीत होती हैं, लेकिन सामूहिक रूप से एक व्यापक जनभावना के उभरने का संकेत देती हैं।

- सीजेपी की तर्ज पर यह मुहिम भी सोशल मीडिया पर शुरु हुई, जब एक छात्र वेदांत ने इंस्टाग्राम पर रिज़र्वेशन हटाओ आंदोलन (आर.एच.ए.) पेज शुरु किया और अब इसके 59 लाख फॉलोअर्स हैं और कई चर्चित हस्तियों ने भी इसे समर्थन दिया है।
- आर.एच.ए. के समर्थक जंतर मंतर पर धरना-प्रदर्शन करने की योजना भी बना रहे हैं।

ऑनलाइन दुनिया में आरक्षण विरोधी अभियान को तेजी से समर्थन मिल रहा है। "रिज़र्वेशन हटाओ आंदोलन (आरएचए)" का इंस्टाग्राम पेज, जिसने सीजेपी के नेतृत्व वाले आंदोलनों के शांत पड़ने के बाद लोकप्रियता हासिल करनी शुरू की, अब लगभग 59 लाख फॉलोअर्स के साथ जाति-आधारित आरक्षण के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहा है और इसकी समीक्षा व तार्किक पुनर्संरचना की मांग कर रहा है। आरएचए ने पिछले सप्ताह महाराष्ट्र के नागपुर में अपना पहला जमीनी प्रदर्शन भी आयोजित किया।

इसके कुछ ही दिनों बाद जयपुर में राजपूत संगठन "श्री राजपूत करणी सेना" के सदस्यों का आंदोलन उग्र हो गया। संगठन के कार्यकर्ता, अब स्थगित किए जा चुके, यूजीसी के जातीय समानता संबंधी नियमों के विरोध में सड़कों पर उतरे और पुलिस से उनकी झड़प हुई। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत का भी आरोप लगाया गया। करणी सेना के नेताओं ने अपने आराध्य देवताओं की शपथ लेकर स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा को वोट न देने का संकल्प लिया है।

इन घटनाक्रमों को एक साथ देखें तो स्पष्ट होता है कि आरक्षण विरोधी आवाज़ें अब ऑनलाइन और जमीनी स्तर, दोनों पर अधिक मुखर होती जा रही हैं। लेकिन यह आंदोलन विभिन्न समूहों में बंटा हुआ दिखाई देता है।

हर्ष दुबे जंतर-मंतर पहुंचकर आंदोलन का नेतृत्व करने की तैयारी में हैं। वहीं, आरएचए इंटरनेट पर आरक्षण विरोधी अभियान को आगे बढ़ा रहा है, जबकि श्री राजपूत करणी सेना जयपुर की सड़कों पर अपनी अलग लड़ाई लड़ रही है।

फिर भी यह तो साफ है कि आरक्षण विरोधी भावना पहले की तुलना में अधिक मजबूत होती जा रही है। शिक्षाविद एवं लेखक आनंद रंगनाथन, पत्रकार एवं कंटेंट क्रिएटर अजीत भारती तथा लेखिका-निर्देशक अनुराधा तिवारी जैसी प्रमुख हस्तियां भी उस आरएचए मंच से जुड़ गई हैं, जिसकी शुरुआत कुछ सप्ताह पहले वेदांत नामक एक छात्र ने की थी।

इन प्रमुख आवाजों द्वारा मांगों की एक सूची भी जारी की गई है।

राजनेता हमेशा की तरह आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर केवल श्री राजपूत करणी सेना और हर्ष

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को जमानत देने से इंकार किया

जोधपुर, 6 अगस्त (कासं)। नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में दोषी आसाराम की अंतरिम मेडिकल बेल की अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। याचिका को पेंडिंग रखा गया है। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर नहीं लग रहा है कि अंतरिम जमानत की जरूरत है। आसाराम तबीयत बिगड़ने पर दोबारा अंतरिम जमानत की मांग कर सकता है।

- अदालत ने कहा कि मैडिकल रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम जमानत की जरुरत नहीं लग रही।

एम्स की ओर से प्रस्तुत आसाराम बापू की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, आसाराम बापू को अस्पताल में भर्ती रखने की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

होर्मुज़ को खोलने के लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था पर काम कर रहा है ईरान

दक्षिण में ओमान तथा उत्तर में ईरान के समुद्री मार्गों का उपयोग करके वैकल्पिक मार्ग तैयार करने पर ओमान व ईरान में वार्ता चल रही है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 अगस्त। अपने दावों के विपरीत, ऐसा लगता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में जारी गतिरोध का समाधान निकालने के लिए भारी दबाव में है। उसका तेल और अन्य सामान वैश्विक बाजारों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ईरानी बंदरगाहों और होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले मार्ग पर अमेरिका की नाकाबंदी ने ईरान की अर्थव्यवस्था और उसकी वित्तीय स्थिति पर गंभीर असर डाला है।

इसी संदर्भ में, ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा खोलने के लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था पर काम कर रहा है। इसके तहत, वह दक्षिण में ओमान तथा उत्तर में ईरान के समुद्री मार्गों का उपयोग करके आने-जाने के वैकल्पिक रास्ते तैयार कर रहा है।

पूर्व में ईरान ने अपने उत्तरी समुद्री मार्गों, जो उसकी तटरेखा के पास हैं, के अलावा किसी अन्य रास्ते या दोबारा खोलने की संभावना को खारिज कर दिया था। तथापि, ओमान इस संकरे समुद्री मार्ग के अपनी तरफ के वैकल्पिक रास्ते विकसित करने में सक्रिय रहा है।

ये व्यवस्थाएं ईरान और ओमान के बीच सीधे तय की जा रही हैं। इसमें अमेरिका को शामिल नहीं किया गया है और उसकी कोई भूमिका नहीं है।

- इन मार्गों से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों से शुल्क वसूलने का भी प्रावधान है, हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों के उपयोग पर शुल्क वसूलना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है।
- ओमान पहले शुल्क लेने के खिलाफ था, पर, अब वह इससे सहमत होता दिख रहा है, लेकिन शुल्क की रेट पर मतभेद है। ईरान माल की कीमत का 5 से 7 प्रतिशत शुल्क चाहता है, वहीं ओमान ने 3 प्रतिशत का प्रस्ताव रखा है।
- असल में अमेरिका ने होर्मुज़ में नाकाबंदी कर रखी है और ईरान का सामान अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार तक नहीं पहुँच पा रहा है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसलिए ईरान पर भारी दबाव है, कोई रास्ता तलाशने का।

हालांकि ईरान और ओमान के बीच नई व्यवस्था में इन मार्गों से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों से शुल्क लेने का प्रावधान रखा गया है।

यह अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों के चलन के विपरीत है और अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्तों के उपयोग के लिए शुल्क लेना अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। इस वर्ष फरवरी के अंत में ईरान और अमेरिका-इज़रायल के बीच युद्ध शुरू होने से पहले तक इस जलडमरूमध्य से गुजरने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता था।

अमेरिका और ईरान के बीच विवाद का एक प्रमुख मुद्दा यही शुल्क था। अमेरिका का कहना है कि होर्मुज़ स्ट्रेट के उपयोग के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगाया जा सकता। वहीं ईरान इसे तुरुप का इक्का और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का एक जरिया मानता है। खाड़ी के अरब देशों ने भी जहाजों से शुल्क लेने के विचार का जोरदार विरोध किया है।

ओमान पहले इस मार्ग के उपयोग पर शुल्क लेने के खिलाफ था, लेकिन अब वह भी इस पर सहमत होता दिखाई दे रहा है। जहां ईरान माल की कीमत का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीरज डांगी राज्यसभा में कांग्रेस के सचेतक बने

नई दिल्ली, 6 अगस्त। कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को राज्यसभा में पार्टी का सचेतक (व्हिप) नियुक्त किया है। यह नियुक्ति राज्यसभा सांसद रजनी अशोकराव पाटिल के सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त हुए पद पर की गई है।